सच कहने की ताकत

साप्ताहिक समाचार पत्र

जालंधर ब्रीज

प्रेरणा
कर्तव्य और कर्म जिसके साथ है, बस समझो जीत उसके पास है।

दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं

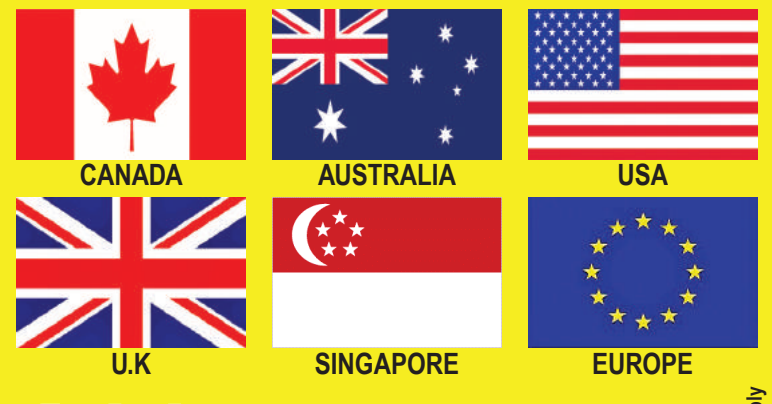

www.jalandharbreeze.com • JALANDHAR BREEZE • WEEKLY • YEAR-4 • 21 OCTOBER TO 27 OCTOBER 2022 • VOLUME-14 • PAGE-4 • RATE-3.00/- • RNI NO.: PUNHIN/2019/77863

Lic No : 933/ALC-4/LA/FN:1184
INNOVATIVE TECHNO INSTITUTE
INNOVATIVE TECHNO INSTITUTE CONSULTING DESIGN TRAINING
ISO CERTIFIED 2015 COMPANY
✓ STUDY ✓ WORK ✓ SETTLE IN ABROAD
Low Filing Charges &
*Pay Money after the visa
•IELTS •STUDY ABROAD
CANADA AUSTRALIA USA U.K SINGAPORE EUROPE
E-mail : hr@innovativetechin.com • Website : www.innovativetechin.com • FB/Innovativetechin • Contact : 9988115054 • 9317776663
REGIONAL OFFICE : S.C.O No. 10 Gopal Nagar, Near Batra Palace, Jal. HEAD OFFICE : S.C.O No. 21-22, Kuldip Lal Complex, Highway Plaza GT Road, Adjoining Lovely Professional University. Phagwara.
*T&C apply

10 लाख लोगों को मिलेगी नौकरी, 22 अक्टूबर को 'रोजगार मेला'

भर्ती अभियान की शुरूआत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी

नई दिल्ली : दिवाली से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के युवाओं को बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। भले ही एक ओर बेरोजगारी को लेकर लगातार विपक्ष मोदी सरकार से सवाल पूछ रहा है। लेकिन देश के 10 लाख युवाओं को नौकरी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोजगार मेला लॉन्च करने जा रहे हैं। इसके पहले चरण में 22 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के 75000 युवाओं को जॉब सर्टिफिकेट देंगे। यह इस योजना का पहला चरण है रोजगार मेले के तहत देश के विभिन्न मंत्रालयों विभागों और संगठनों में खाली पदों को भरने के लिए योग्य उम्मीदवार का चयन किया जाएगा। नौकरी की तलाश में जुटे युवाओं के पास रोजगार का यह शानदार मौका है। आपको बता दें कि उस दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 10 लाख लोगों को नौकरी देने का ऐलान किया था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कहते रहे हैं कि अपना देश युवाओं का देश है। देश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनकी सरकार लगातार काम कर रही है। अपने नागरिकों के कल्याण के प्रति मोदी सरकार लगातार प्रतिबद्धता दिखाती रही है।

इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी का यह बड़ा कदम माना जा रहा है। एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने और नागरिकों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री की निरंतर प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इसमें यह भी कहा गया है कि प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार सभी मंत्रालय और विभाग मिशन मोड में मौजूदा रिक्तियों को भरने की दिशा में काम कर रहे हैं।

इससे पहले जून में पीएम मोदी ने सभी केंद्रीय विभागों और मंत्रालयों में मानव संसाधन की स्थिति की समीक्षा की थी और निर्देश दिया था कि सरकार अगले 1.5 साल में मिशन मोड में 10 लाख लोगों की भर्ती करे। ग्रुप ए (राजपत्रित) श्रेणी में 23,584 रिक्त पद, ग्रुप बी (राजपत्रित) में 26,282, ग्रुप बी (अराजपत्रित) में 92,525 और ग्रुप सी (अराजपत्रित) में 8.36 लाख पद हैं। अकेले रक्षा मंत्रालय में ग्रुप बी (अराजपत्रित) के 39,366 और ग्रुप सी के 2.14 लाख पद खाली हैं। रेलवे में ग्रुप सी के 2.91 लाख और एमएचए में 1.21 लाख ग्रुप सी (अराजपत्रित) पद खाली हैं।

मानसा की अदालत में पेश हुए मान, देश की न्याय प्रणाली पर प्रकटाया भरोसा

• **जालंधर ब्रीज.मानसा**

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज कहा कि इस साल के शुरू में हुये विधान सभा मतदान में अपनी करारी हार से दुखी और घबराऐ कांग्रेसी नेता मानहानि को अब लोक भलाई और राज्य की तरक्की के लिए अथक मेहनत करने वालों के विरुद्ध बदला लेने के साधन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ स्थानीय अदालत में पेश होने के बाद पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि जो नेता अपने निजी हितों के लिए लोगों के जनादेश के साथ धोखा और दग़ा करते हैं, वह अब हमारे विरुद्ध मानहानि केस दायर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वास्तव में ऐसे व्यक्ति राज्य सरकार के लोक समर्थकी फ़ैसले के मद्देनजऱ सरकार की बढ़ रही

मकबूलियत से डर रहे हैं। भगवंत मान ने कहा कि यह केस लोगों की भलाई के लिए अथक मेहनत कर रही हमारी पार्टी के हक में आए फ़ैसले के कारण रंजिश के तौर पर दायर किये जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे मामले उनको पंजाब और इसके लोगों की भलाई के लिए फ़ैसले लेने से नहीं रोक सकेंगे। भगवंत मान ने कहा कि वह पंजाब के हितों के लिए ऐसे किसी भी केस का सामना करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि यह कितना हास्यप्रद है कि जिन लोगों ने देश को लम्बे समय तक बर्बाद किया, वह अब लोक भलाई के लिए काम करने वालों के विरुद्ध मानहानि को साधन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने सवाल किया कि कई दशकों से देश को लूटने वालों के खि़लाफ़ मानहानि केस क्यों नहीं दर्ज किये जाते। इसी तरह उन्होंने कहा कि जो लोग सच्चे देश भक्तों को आतंकवादी करार देते हैं, उनके खि़लाफ़ केस क्यों नहीं दर्ज किये जा रहे। भगवंत मान ने कहा कि जो नेता लोगों की दुख तकलीफ़ों दूर करके लोगों की ज़िंदगी को बदलने के लिए अथक मेहनत कर रहे हैं, वह आतंकवादी कैसे हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि दुख की बात यह है कि ऐसे शरारती तत्वों के विरुद्ध कोई मानहानि जैसी कार्यवाही नहीं होती।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब भी उनके विरुद्ध सम्मन जारी किये जाएंगे तो वह अदालत में पेश होंगे। भगवंत मान ने कहा कि उनको देश की न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि अदालतें बहुत आदरणीय हैं और वह अदालत के हर फ़ैसले की पालना करेंगे।

ब्रिटेन की पीएम ने दिया इस्तीफा

लंदन : ऋषि सुनक बनाम लिज ट्रेस यानी ब्रिट्रेन के प्रधानमंत्री बनने की रेस पांच सितंबर को खत्म हो गई। जब लिज ट्रस ने 20 हजार से ज्यादा वोटों से ऋषि सुनक को मात देकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद की पहली पसंद बनीं। लेकिन सत्ता संभालने के 45 दिनों के भीतर ही हालात ऐसे बने कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल की लिज ट्रस के इस्तीफे के बाद आगे क्या? माना जा रहा है कि अब कंजर्वेटिव पार्टी के नए नेता को दोबारा चुना जाएगा। हालांकि अगर सत्तारूढ़ पार्टी के सांसद चाहें तो केवल वे ही

वोटिंग के जरिए नए नेता को चुन सकते हैं। ऐसे में बोरिस जॉनसन के खेमे के सांसद कोई आपत्ति न करें तो ऋषि सुनक का ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना जाना तय माना जा रहा है। सरकारी स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने वाली 46 साल की लिज ट्रस की जिंदगी व राजनीतिक सफर काफी रोचक रहा है। उनके पिता गणित के प्रोफेसर और मां एक नर्स थीं।

पैरोल पर बाहर आए डेरा प्रमुख का ऑनलाइन प्रवचन, कुछ भाजपा नेता हुए शामिल

करनाल : पैरोल पर बाहर आया डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह पिछले कुछ दिनों से ऑनलाइन सत्संग कर रहा है जिनमें भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की हरियाणा इकाई के कई नेताओं ने भाग लिया है। राम रहीम के पैरोल पर बाहर रहने का समय एक बार फिर क्षेत्र में कुछ चुनावों की तारीखों से मेल खा रहा है। इस वर्ष यह ऐसा तीसरा उदाहरण है। हरियाणा में अगले महीने पंचायत चुनाव और आदमपुर विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव होने हैं। डेरा प्रमुख हरियाणा में 46 नगरपालिकाओं के चुनाव से पहले जून में एक महीने की पैरोल पर जेल से बाहर आया था। डेरा प्रमुख को पंजाब विधानसभा चुनाव से करीब दो हफ्ते पहले सात फरवरी से तीन सप्ताह की छुट्टी दी गई थी। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बड़ी संख्या में सिरसा डेरा के अनुयायी हैं।

सिरसा डेरा प्रमुख राम रहीम (55) उत्तर प्रदेश के बागपत में डेरा के बरनावा आश्रम से ऑनलाइन सत्संग कर रहा है। हरियाणा के उप-विधानसभा अध्यक्ष रणबीर गंगवा बुधवार को हिसार में ऑनलाइन प्रवचन सुनने के लिए डेरा के अनुयायियों की एक सभा में मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने सिरसा डेरा से अपने परिवार के जुड़ाव की चर्चा की।

पंजाब-हरियाणा में और बढ़े पराली जलाने के मामले

किसानों को पराली जलाने से रोकने में सरकार पूरी तरह विफल

• **जालंधर ब्रीज.** विशेष रिपोर्टर

किसानों को पराली जलाने से रोकने में पंजाब सरकार अब तक नाकाम रही है। बजट की कमी के चलते सरकार की पराली प्रबंधन की योजनाएं भी अधर में हैं। अब किसानों ने सरकार की पराली न जलाने की अपील भी ठुकरा दी है। मुआवजे की मांग को लेकर किसान सड़कों पर आ गए हैं।

धान की फसल तैयार होते ही पंजाब और पड़ोसी राज्य हरियाणा में पराली जलाने की घटनाएं बढ़ने लगी है। किसान पराली को आग के हवाले कर रहे हैं। हरियाणा में अब तक 83 और पंजाब में 750 से अधिक मामले दर्ज किए जा चुके हैं। हरियाणा सरकार पराली जलाने के आरोपी किसानों के खिलाफ कई मामले दर्ज कर चुकी है। वहीं, पंजाब में किसानों को पराली जलाने से रोकने में नाकाम रही है।

पंजाब सरकार का खजाना खाली है, जिसकी वजह से वह खराब फसलों का मुआवजा नहीं दे पा रही है। किसान पराली ना जलाएं इसके लिए सरकार की प्रस्तावित मुआवजा योजना भी कागजों में लटकी हुई है। केंद्र सरकार ने भी पंजाब सरकार की मुआवजा योजना पर सहमति नहीं दी है। केंद्र सरकार सरकार का कहना है कि पराली प्रबंधन के लिए वह पहले से ही किसानों को आर्थिक सहायता दे रही है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पराली की समस्या को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में तय हुआ कि प्रभावित जिलों में कलेक्टरों की जवाबदेही तय की जाएगी। साथ ही राज्यों को तुरंत प्रभाव से जरूरी कदम उठाने होंगे। पराली गलाने के लिए पूसा द्वारा तैयार की गई तकनीक बायो डी- कंपोजर का उपयोग बढ़ाया जाए। बैठक में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरूषोत्तम रूपाला भी मौजूद रहे। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली सरकार समेत तीनों केंद्रीय मंत्रालयों के अधिकारी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली व एनसीआर में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, बिजली मंत्रालय के अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे।

पराली जलाने की घटनाओं में हो सकता है इजाफा : राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों का मानना है कि बेमौसमी बरसात की वजह से एक तरफ जहां पराली में नमी की मात्रा बढ़ेगी वही फसल की कटाई भी देरी से होगी। अबकी बार फसल क्योंकि पिछले साल की तुलना में ज्यादा रकबे पर उगाई गई है। इसलिए पराली जलाने की घटनाओं में इजाफा हो सकता है।

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि पराली की समस्या से प्रभावित जिलों में राज्य सरकारों को कलेक्टरों की जवाबदेही तय करने की जरूरत है। बैठक में कहा गया कि केंद्र की ओर से राज्यों को पिछले चार साल में 2.07 लाख मशीनें दी गई है और चालू वर्ष के दौरान आपूर्ति की जाने वाली 47 हजार मशीनों का प्रभावी उपयोग होना चाहिए। पराली जलाने के कारण वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए केंद्रीय योजना के तहत पंजाब, हरियाणा, यूपी, दिल्ली को वित्तीय सहायता भी दी जा रही है। चालू वर्ष के दौरान केंद्र द्वारा अब तक 601.53 करोड़ रुपये पहले ही जारी किए जा चुके हैं। साथ ही पिछले चार साल में दी गई राशि में से भी करीब 900 करोड़ रुपये राज्यों के पास उपलब्ध है।

पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि केंद्र द्वारा दी गई दो लाख से ज्यादा मशीनें पर्याप्त है, जरूरी है कि इनका पूरा उपयोग किया जाए, जिससे समस्या का समाधान संभव है। केंद्र द्वारा प्रदूषण के अन्य कारकों को लेकर भी विचार किया गया है। उन्होंने विशेषकर पंजाब में पराली जलाने से रोकने के लिए प्रभावी नियंत्रण पर बल देते हुए वहां के मुख्य सचिव को तत्काल समुचित कार्यवाही करने के साथ ही पूसा डी-कंपोजर के उपयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया।

किसानों को छोड़ गुजरात में व्यस्त है पंजाब सरकार : किसानों की दुर्दशा देखकर अब विपक्ष भी उनके पक्ष में खुलकर सामने आ गया है। अकाली दल ने सरकार को कठघरे में खड़ा करते हुए आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान उनके कैबिनेट मंत्री और विधायक गुजरात पलायन कर चुके हैं और किसान भगवान भरोसे हैं।

वहीं, किसानों तक मशीनों की पहुंच नहीं : किसानों को अब पंजाब सरकार के झूठे दिलासों पर यकीन नहीं है। पराली प्रबंधन के लिए मशीनों की उपलब्धता पर किसान सवाल खड़े कर रहे हैं। यह मशीनें किसानों की पहुंच से अभी भा बाहर हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के कार्यकाल के दौरान तो पंजाब में पराली प्रबंधन की मशीनों से जुड़ा डेढ़ सौ करोड़ रुपये का घोटाला भी सामने आया था।

अब आने वाले दिनों में यह देखना होगा कि पराली जलने से बढ़ने वाली प्रदूषण से सरकार जनता को कैसे निजात दिलाएगी।

किसानों ने ठुकराई पराली न जलाने की अपील

एक तरफ किसान जहां बेमौसमी बरसात की वजह से खराब हो चुकी धान और हरी सब्जियों की फसलों पर मुआवजे की मांग कर रहे हैं। किसानों ने सरकार की पराली न जलाने की अपील भी ठुकरा दी है। काफी अरसे से मुआवजे की बाट जोह रहे किसान अब सड़कों पर आ गए हैं। नाराज किसानों द्वारा पिछले कई दिनों से मुख्यमंत्री भगवंत मान के संगरूर आवास के बाहर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। मोहाली के जंगपुरा गांव के किसान जगदीश सिंह कहते हैं कि अगर सरकार चाहती है कि हम पराली ना जलाएं तो हमें मुआवजा मिलना चाहिए।

बायो-डीकंपोजर छिड़काव पर जोर

राज्यों को कहा गया कि पराली प्रबंधन के लिए दी जाने वाली पूरी राशि का उपयोग किया जाए। बायो-डीकंपोजर छिड़काव का व्यापक उपयोग होना चाहिए। पंजाब के अमृतसर व तरनतारण जिलों में पराली जलाने पर प्रभावी नियंत्रण कर लिया जाए तो 50 प्रतिशत समस्या का समाधान हो सकता है क्योंकि इन दो जिलों में सबसे ज्यादा समस्या सामने आ रही है। इन चारों राज्यों में पराली की समस्या के प्रभावी नियंत्रण से अन्य राज्यों में भी समस्या का विस्तार नहीं होगा। बैठक में कहा गया कि योजनाबद्ध तरीके से अगर प्रयास किए जाते हैं तो पशुओं के लिए चारे की भी उपलब्धता में आसानी होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि 4 नवंबर को पूसा कार्यशाला की जा रही है, जिसमें पंजाब व आसपास के किसानों को बुलाया गया है, पंजाब के वरिष्ठ अधिकारी भी इसमें शामिल हों ताकि पूसा डी-कंपोजर को लेकर उनका भ्रम दूर हो सके। पराली गलाने के लिए पूसा डी-कंपोजर सबसे सस्ता और प्रभावी उपाय है और इसका प्रयोग बढ़ाना होगा।

पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए ये देश फ्री में दे रहा है हवाई टिकट

• **जालंधर ब्रीज.** फीचर

कोरोना महामारी के बाद से कई देशों के पर्यटन पर असर पड़ा। कई देशों में पर्यटन इंडस्ट्री को काफी नुकसान हुआ। कोरोना वायरस फैलने के बाद देशों में विदेशी पर्यटकों पर रोक लगा दी। हालांकि जब लॉकडाउन खुला तो कई देशों के पर्यटकों को भी विदेशियों से लिए खोल दिया गया। लेकिन कोविड काल के बाद आई मंदी और संक्रमण के डर से लोग दूसरे देशों में घूमने के लिए यात्रा पर नहीं जा रहे। ऐसे में एक देश विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शानदार ऑफर देने की व्यवस्था कर रहा है। जो यात्री विदेश घूमने जाना चाहते हैं, उनके लिए मुफ्त सफर की तैयारी हो रही है। हॉन्ग कॉन्ग ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजना निकाली है। इस योजना के तहत हांगकांग आने वाले यात्रियों को मुफ्त सफर का लाभ मिलेगा।

कोविड दौर से पहले तक हॉन्ग कॉन्ग में हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक घूमने आते थे। कोरोना के बाद यहां पर्यटकों की संख्या कम हुई। अब तक चीन की जीरो कोविड पॉलिसी हॉन्ग कॉन्ग में लागू थी। यह दुनिया के सबसे सख्त क्वारंटाइन नियम थे, लेकिन पिछले महीने हॉन्ग कॉन्ग ने क्वारंटाइन नियमों में ढील दी है।जिसके तहत अब विदेश से आने वाले यात्रियों को होटल में क्वारंटाइन करने या हॉन्ग कॉन्ग की फ्लाइट लेने से पहले कोविड टेस्ट कराकर नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है।

हॉन्ग कॉन्ग पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यात्रियों को मुफ्त हवाई टिकट देने की भी तैयारी में है। हवाई अड्डा प्राधिकरण हॉन्ग कॉन्ग 5 लाख मुफ्त हवाई टिकट बांटेगा। मुफ्त टिकट अगले साल से बांटे जाने हैं। इस योजना के जरिए हॉन्ग कॉन्ग लगभग

में हांगकांग ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजना निकाली है। हवाई अड्डा प्राधिकरण हांगकांग 500,000 मुफ्त हवाई टिकट देने जा रहा है। ये टिकट अगले साल बांटे जाएंगे। इन टिकटों की कीमत करीब 21 अरब 10 करोड़ से ज्यादा है।

हॉन्ग कॉन्ग ने विमानन उद्योग की मदद के लिए राहत पैकेज के हिस्से के रूप में घरेलू एयरलाइनों से हवाई टिकट खरीदे थे। इसका उद्देश्य एयरलाइन्स के लिए नकदी का इंतजाम करना था। चूंकि हॉन्ग कॉन्ग ने कोरोना काल में लगे सख्त नियमों को वापस ले लिया है, ऐसे में दोबारा पर्यटकों की संख्या को बढ़ाने के लिए मुफ्त हवाई टिकट देने की योजना बनाई जा रही है।

कई सारे कोविड नियमों को हटा दिया गया है लेकिन हांगकांग आने वाले यात्रियों को अभी भी कुछ नियमों का पालन करना होगा। इसके लिए हांगकांग आने वाले विदेशी यात्रियों को प्रवेश से पहले टीकाकरण प्रमाणपत्र, निगेटिव पीसीआर रिपोर्ट जमा करनी होगी। यात्रियों को तीन दिवसीय सेल्फ क्वारंटीन अवधि से गुजरना होगा।

यहां के मशहूर पर्यटन स्थलों में हांगकांग डिज्नीलैंड,मैडम तुसाद म्यूजियम, टेंपल स्ट्रीट नाइट मार्केट, मॉंग-कॉक, स्टेनली मार्केट तथा स्टैनली बीच, ओशियन पार्क और पीक टावर है।

TRAVLING

FASSION+

जान्हवी कपूर की तरह साड़ी पहन दिवाली पर हो तैयार

लाल रंग की साड़ी में जान्हवी कपूर

त्योहार पर ट्रेडिशनल ड्रेस में तैयार होना अच्छा लगता है। खासतौर पर साड़ी और लहंगा पहनना लड़कियों को पसंद आता है। अगर आप इस दिवाली साड़ी पहनकर पूजा के लिए तैयार होना चाहती हैं। तो जान्हवी कपूर के इन साड़ी वाले लुक को ट्राई कर सकती हैं। जान्हवी कपूर वैसे तो इन दिनों बेहद बोल्ड और ग्लैमरस लुक में फैंस को रिझाने में लगी हैं। लेकिन बात जब पारंपरिक कपड़े की आती है तो अक्सर वो साड़ी पहने दिख जाती हैं। पिछले दिनों ही लाल रंग की साड़ी में उनका खूबसूरत लुक सामने आया था। जिसे उनके फैंस ने काफी पसंद किया था। तो अगर आप भी जान्हवी कपर की फैन हैं तो उनके इन साड़ी लुक की नकल जरूर करें।

अगर आप पहली बार साड़ी पहनने वाली हैं तो जान्हवी कपूर की तरह हल्के फैब्रिक की साड़ी को चुनें। जिसे आप आसानी से कैरी कर सकें। हैवी एंब्रायडरी वाले ब्लाउज और मैचिंग के बॉर्डर वाली इस सुर्ख लाल रंग की साड़ी में जान्हवी कपूर बेहद खूबसूरत लग रही हैं। आप चाहे तो मेकअप से लेकर हेयरस्टाइल तक पूरे लुक को कॉपी कर सकती हैं। इसमे हर लड़की खूबसूरत दिखेगी।

वैसे तो काले रंग की साड़ी त्योहारों पर शुभ नहीं मानी जाती। लेकिन अगर आप इस लुक को चाहे तो कॉपी कर सकते हैं। नेट फैब्रिक की साड़ी संग बैकलेस डिजाइन के ब्लाउज को जान्हवी ने मैच किया है। वहीं बात करें मेकअप की तो विंग्ड आईलाइनर और सिंपल स्लीक सी पोनीटेल आपको आरामदायक लुक देगी। जिससे आपका पूरा ध्यान अपनी साड़ी को संभालने में रहेगा और बालों को बार-बार ठीक करने का झंझट नहीं झेलना पड़ेगा।

सफेद रंग की फ्लोरल प्रिंट साड़ी में जान्हवी कपूर का लुक हमेशा की तरह ही खूबसूरत है। जिसे उन्होंने स्पैगेटी स्लीव वाले ब्लाउज के साथ पेयर किया है। वहीं हेयरस्टाइल से लेकर मेकअप तक सबकुछ आप कॉपी कर इस दिवाली गॉर्जियस अंदाज में तैयार हो सकती हैं।

वैसे तो जान्हवी कपूर ने इस साड़ी संग बेहद बोल्ड ब्लाउज को पहना है। लेकिन आप चाहें तो इन दिनों में ट्रेंड में चल रही सिकुइन वर्क वाली साडी को भी पहन सकती हैं। साथ में स्लीवलेस डिजाइन के ब्लाउज को मैच करें। हालांकि जान्हवी कपूर की तरह सिल्वर कलर की हैवी ईयररिंग्स और पिंक ग्लॉसी लिपस्टिक को जरूर लगाएं।

प्रिंटेड साड़ी में भी कैसे खूबसूरत दिखा जा सकता है। ये टिप्स आप जान्हवी कपूर की इन तस्वीरों से ले सकती हैं। ग्रीन प्रिंटेड साड़ी संग मैचिंग के ब्लाउज को जान्हवी ने पिंक शेड के चांदबाली के साथ मैच किया है। वहीं बालों को वेवी कर्ली कर खुला रखा है। जिसके साथ मैट फिनिश मेकअप बेहद खूबसूरत लुक देने के लिए काफी दिख रहा है।

दिवाली पर घर आ रहे मेहमान तो बनाएं केले के पकौड़े

दिवाली का त्योहार लगभग पूरे सप्ताह ही चलता है। पूजा और खरीदारी के साथ ही लोग एक दूसरे से मिलकर त्योहार की खुशी एक दूसरे के साथ बांटते हैं। अगर आपके घर भी इस दिवाली मेहमान आने वाले हैं। या फिर आप घर में पार्टी दे रही हैं। तो कच्चे केले के पकौड़े को स्नैक्स में बना सकती हैं। ये रेसिपी काफी आसान है और इसका स्वाद भी हर किसी को पसंद आएगा। तो अगर आप मेहमानों को कुछ हटके पकवान खिलाना चाहती हैं तो केले के पकौड़ों को बनाकर तैयार करें। तो चलिए जानें क्या है बनाने की विधि।

कच्चे केले के पकौड़े बनाने की सामग्री

एक कप बेसन, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चुटकी हींग, एक चम्मच जीरा, एक चम्मच लहसुन पाउडर, नमक स्वादानुसार, दो कच्चे केले, तलने के लिए।

कच्चे केले के पकौड़े बनाने की विधि

सबसे पहले कच्चे केले के छिलके को निकाल दें। फिर इनके चौकोर टुकड़े काट लें। अब दूसरे कटोरे में बेसन लें। इसमे हींग, नमक, लाल मिर्च पाउडर, जीरा, लहसुन पाउडर डालकर मिक्स करें। पानी डालकर गाढ़ा घोल तैयार करें। अब कड़ाही में तेल गर्म करें। जब तेल गर्म हो जाए तो इसमे कच्चे केले के टुकड़ों को डालें। कच्चे केले के एक-एक टुकड़े को लेकर बेसन के घोल में डुबोएं। जब इस पर बेसन अच्छी तरह से लग जाए तो इन्हें गर्म तेल में डालें। सुनहरा होने तक मध्यम आंच पर तलें।

आप चाहें तो कच्चे केले के साथ ही बैंगन, गोभी और पालक जैसी सब्जियां भी डाल सकती हैं। इन सारी चीजों को अलग-अलग काटकर बेसन के घोल में लपेट कर तलें। फिर इसे भी कच्चे केले के पकौड़ों के साथ ही सर्व करें। पकौड़े के साथ आप चाहें तो टोमैटो सॉस परोंसे। या फिर हाथ से बनीं पुदीने और दही की चटनी को भी परोस सकती हैं। इसका स्वाद इन पकौड़ों के साथ टेस्टी लगेगा।

सावधान : मच्छर भगाने के लिए क्या आप भी जलाते हैं क्वाइल्स?

देश के ज्यादातर हिस्सों में इन दिनों मच्छर जनित बीमारियों का खतरा बढ़ता देखा जा रहा है। अक्तूबर के महीने में डेंगू-चिकनगुनिया जैसी गंभीर जानलेवा बीमारियों के कारण हजारों लोग प्रभावित होते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं, ये बीमारियां कुछ स्थितियों में जानलेवा तक हो सकती हैं, ऐसे में सभी लोगों को इनसे बचाव के उपाय करते रहना चाहिए। इसके लिए मच्छरों को पनपने से रोकें और इनके काटने से बचाव करें। इसके लिए क्या आप भी

STUDY

मच्छर भगाने वाले क्वाइल्स जलाते हैं? यह शरीर के लिए कई प्रकार से नुकसानदायक हो सकता है।

मच्छर भगाने वाले क्वाइल्स को जलाने से निकलने वाले धुंए से मच्छर तो मर जाते हैं पर ये कमरे के वातावरण को प्रदूषित कर देता है जिसके कारण कई प्रकार की बीमारियों के विकसित होने का खतरा हो सकता है।

डॉक्टर्स कहते हैं, क्वाइल्स से निकलने वाला प्रदूषित धुंआ जब सांस के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है तो इससे कई प्रकार की बीमारियों के विकसित होने का जोखिम हो सकता है। अध्ययनों में पाया गया है कि इसके कारण फेफड़ों को क्षति पहुंच सकती है जो सांसों की कई प्रकार की समस्याओं का कारण बनता है। आइए जानते हैं कि क्वाइल्स जलाने से किस प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा हो सकता है। इस स्थिति में मच्छरों से बचने के लिए क्या किया जाना चाहिए?

क्वाइल्स से निकलने वाले धुंए से सेहत को किस प्रकार के नुकसान हो सकते हैं, इस बारे में जानने के लिए किए गए अध्ययन में वैज्ञानिकों ने पाया कि लगातार इसका उपयोग इनडोर प्रदूषण को बढ़ा सकता है। एक कॉइल को जलाने से फॉर्मलाडेहाइड का उत्सर्जन 51 सिगरेट जलाने के बराबर होता है। इस रसायन का उपयोग कई प्रकार के घरेलू उत्पादों में तीक्ष्ण सुगंध के लिए किया जाता है।

अध्ययनों में इसे सेहत के लिए बहुत हानिकारक पाया गया है, इससे कैंसर का भी जोखिम हो सकता है। क्वाइल से निकलने वाले धुंए के लगातार संपर्क में रहने के कारण फेफड़े के कैंसर के विकसित होने का खतरा भी बढ़ जाता है।

क्या शाकाहारी लोगों की लंबी होती है आयु? अध्ययन में बड़ा खुलासा

HEALTH+

पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक स्तर पर शाकाहारी भोजन के प्रति लोगों को रुझान बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। पर्यावरणीय या स्वास्थ्य कारणों के चलते बड़ी संख्या में लोगों ने वेजिटेरियन डाइट शिफ्ट किया है। अध्ययनों से पता चलता है कि शाकाहारी चीजों यानी पौधों से प्राप्त खाद्य पदार्थों के सेवन की आदत शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की आसानी से प्राप्ति में सहायक होती है, साथ ही इससे कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर जैसी समस्याओं के बढ़ने का जोखिम भी कम होता है, ऐसे में इस तरह की डाइट लोगों की पहली पसंद बनती जा रही है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि शाकाहारी आहार का सेवन करने वाले लोगों की जीवन प्रत्याशा भी अधिक होती है। क्या यह वास्तव में सही है?

आहार विशेषज्ञ कहते हैं, शाकाहारी आहार का सेवन रक्त शर्करा को नियंत्रित रखने, हृदय स्वास्थ्य को बेहतर रखने और वजन कम करने में भी मददगार है। हालांकि आयरन और प्रोटीन की आसानी से प्राप्ति के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ मांस-मछली और अन्य मांसाहारी चीजों के सेवन को अधिक प्रभावी मानते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि कौन सा आहार शरीर को स्वस्थ रखने में ज्यादा प्रभावी और लाभकारी है? आइए इस बारे में आगे विस्तार से समझते हैं।

शाकाहारी और मांसाहारी आहार

शाकाहारी या मांसाहारी आहार, शरीर को स्वस्थ रखने में किस प्रकार की चीजों को अधिक फायदेमंद माना जाता है, यह लंबे समय से चर्चा का विषय रही है। कई अध्ययनों के निष्कर्ष में शोधकर्ताओं ने पाया कि शाकाहारी भोजन में अन्य खाने के पैटर्न की तुलना में कम कैलोरी, सेचुरेटेड फैट और कोलेस्ट्रॉल के स्तर में कमी होती है। इसके अलावा इस तरह के आहार में फाइबर, पोटेशियम और विटामिन-सी की भी अधिकता होती है।

शकाहारियों का वजन, मांस खाने वालों की तुलना में कम होता है जिससे उनमें कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा भी कम होता है। ऐसे में शाकाहारी आहार को अधिक स्वस्थ माना जा सकता है।

क्या शाकाहारी लोगों को लंबी होती है जीवन प्रत्याशा?

अध्ययनकर्ताओं ने शाकाहारी और मांसाहारी लोगों के बीच किए गए तुलनात्मक अध्ययन में पाया कि मांसाहारी लोगों की तुलना में शाकाहारी लोगों की जीवन प्रत्याशा अधिक होती है। शोध से पता चलता है कि मांस का सेवन कम करने से आपका जीवनकाल 3.6 वर्ष तक बढ़ सकता है। इसी रिपोर्ट से पता चला है कि पौधों पर आधारित आहार का सेवन करने वाले लोगों की समूह वालों में, 70 वर्ष की आयु से अधिक जीवित रहने की संभावना भी अधिक देखी गई।

क्या कहते हैं अध्ययन?

शोधकर्ताओं ने अध्ययन के निष्कर्ष में पाया कि शाकाहारी लोगों की जीवनशैली, अन्य लोगों की तुलना में ज्यादा बेहतर होती है। शोध यह भी कहते हैं कि शाकाहारी लोगों के धूम्रपान या शराब पीने की संभावना भी कम हो सकती है। बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआई) सामान्य बनाए रखने, नियमित रूप से व्यायाम करने के साथ ऐसे लोगों में कोलेस्ट्रॉल-ब्लड शुगर लेवल के बढ़ने का खतरा भी अपेक्षाकृत कम होता है। पौधों पर आधारित आहार का सेवन करके वजन को कंट्रोल रखने में भी मदद मिल सकती है, जो हृदय रोग-डायबिटीज से बचाव के लिए आवश्यक है।

क्या है शोध का निष्कर्ष?

अध्ययनों के निष्कर्ष में शोधकर्ताओं ने पाया कि शाकाहारी आहार अधिक पौष्टिक होते हैं, चूंकि शाकाहार में पौधे आधारित भोजन जैसे फल, सब्जियां, साबुत अनाज, फलियां, नट और बीज युक्त चीजें शामिल होती है जो शरीर के स्वस्थ विकास और रोग के जोखिम को कम करने में महत्वपूर्ण हैं। शाकाहारी आहार में भरपूर मात्रा में फाइबर, प्लांट प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं। यदि आप मांसाहार का सेवन करते हैं तो इसकी मात्रा को नियंत्रित रखें और रेड मीट का सेवन बहुत अधिक न करें।

पाक की हेकड़ी निकालेगी वायुसेना, बॉर्डर के पास भारत बनाएगा एयरबेस; पीएम मोदी ने रखी आधारशिला

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत दिवस गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने भारत-पाकिस्तान सीमा के पास दीसा में एक नए एयरबेस की आधारशिला भी रखी।

• **जालंधर ब्रीज.** नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत दिवस गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने भारत-पाकिस्तान सीमा के पास दीसा में एक नए एयरबेस की आधारशिला भी रखी और कहा कि यह नया एयरबेस देश की सुरक्षा के लिए एक प्रभावी केंद्र के रूप में उभरेगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि गुजरात भारत में रक्षा का केंद्र बनेगा और भारत की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "मैं स्क्रीन पर देख रहा था कि दीसा के लोग नए हवाई क्षेत्र के निर्माण को लेकर उत्साहित थे। यह हवाई क्षेत्र एक प्रमुख भूमिका निभाएगा। दीसा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से केवल 130 किमी दूर है। यदि हमारी सेना विशेष रूप से हमारी वायु सेना दीसा में मोर्चा संभालती है तो हम पश्चिमी तरफ से आने वाले किसी भी खतरे का बेहतर जवाब दे पाएंगे।" हालांकि उन्होंने इस दौरान पाकिस्तान का नाम नहीं लिया।

इस मौके पर सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न कहा कि यह पहला ऐसा 'डिफेंस एक्सपो' है, जिसमें केवल भारतीय कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। उन्होंने कहा, "अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के साथ-साथ मुक्त व्यापार के लिए समुद्री सुरक्षा आज दुनिया की प्राथमिकता बन रही है।"

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'भारतीय रक्षा उत्पादों का निर्यात पिछले आठ वर्षों में आठ गुना बढ़ा है। रक्षा बल 101 वस्तुओं की एक सूची जारी करेंगे जिनके आयात पर प्रतिबंधित लगाया जाएगा, इसके साथ ही रक्षा क्षेत्र के 411 साजो-सामान व उपकरण ऐसे होंगे जिन्हें भारत में ही बनाया जाएगा।'

एग्री स्टार्टअप्स की सफल पहलों को बढ़ाने 500 करोड़ रु. का एक्सीलरेटर प्रोग्राम शुरु किया जाएगा- तोमर

कृषि स्टार्टअप के लिए बड़ी नीतिगत पहल करते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। पूसा मेला ग्राउंड, दिल्ली में पीएम किसान सम्मान सम्मेलन के दूसरे दिन आयोजित एग्री स्टार्टअप कांफ्रेंस में तोमर ने बताया कि कृषि स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के समग्र मार्गदर्शन के लिए कृषि मंत्री की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय संचालन समिति गठित की जाएगी। एग्री स्टार्टअप्स की सफल पहलों को आगे बढ़ाने व उनके लोकव्यापीकरण के लिए 500 करोड़ रु. का एक्सीलरेटर प्रोग्राम शुरू किया जाएगा।

बड़ी संख्या में उपस्थित एग्री स्टार्टअप प्रतिनिधियों के बीच केंद्रीय मंत्री तोमर ने ऐलान किया कि कृषि सचिव की अध्यक्षता में कार्यकारी समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें संबंधित एजेंसियों जैसे डेयर, डीपीआईआईटी, कृषि इनक्यूबेटर व ज्ञान भागीदारों, कृषि विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, प्रमुख निवेशकों, अन्य हितधारकों के शीर्ष स्तर के अधिकारी शामिल होंगे। साथ ही, कृषि मंत्रालय में कृषि स्टार्टअप के लिए संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में अलग डिवीजन बनाया जाएगा। प्रमाणन एजेंसियों, वित्तीय संस्थानों, कृषि विश्वविद्यालयों आदि के साथ एग्री स्टार्टअप के लिए आवश्यक सभी लिंकेज की सुविधा के लिए सिंगल विंडो एजेंसी के रूप में काम करने के लिए सेल भी बनाया जाएगा। तोमर ने बताया कि एग्री स्टार्टअप द्वारा विकसित उत्पादों की, बाजार की जरूरतों को पूरा करने के लिए ई-नाम व नेफेड जैसी संस्थाओं के साथ एक मार्केटिंग लिंकेज बनाया जाएगा। सभी कृषि स्टार्टअप के लिए एक डेटाबेस तैयार करने और उनके विकास की निगरानी के लिए एक पोर्टल भी विकसित किया जाएगा। तोमर ने कहा कि कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एग्री स्टार्टअप कॉन्क्लेव का आयोजन राष्ट्रीय व क्षेत्रीय स्तर पर करने का प्रयास किया जाएगा।

तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछले आठ साल में लगातार यह कोशिश रही है कि देश की ताकत उभरकर दुनिया के राजनीतिक मंच पर आना चाहिए। हमारे देश के किसान, नौजवान, स्टार्टअप आदि की ताकत को नियोजित तरीके से उभारकर लक्ष्य साधकर काम किया जाएं तो वह दिन दूर नहीं जब भारत सबका मार्गदर्शन करने दुनिया के राजनीतिक मंच पर खड़ा होगा। प्रधानमंत्री मोदी जब-जब भी विदेश गए तो वहां बैठकों के अलावा उन्होंने अप्रवासी भारतीयों से संपर्क कर उनका उत्साहवर्धन किया है। हमारे इन भाइयों-बहनों पर हमें गर्व है जो दुनिया को पोषित करने की क्षमता रखते हैं। मोदी ने आत्मनिर्भर भारत बनाने व वोकल फार लोकल का आह्वान किया है, ऐसे में कभी विदेशी पैन देखकर गर्व करने वाले आज स्वयं सहायता समूह द्वारा बांस से बनाए गए पैन जेब में लगा देखकर गौरव का अनुभव करते हैं। पहले विदेश जाकर नौकरी करने की प्रतिस्पर्धा थी लेकिन आज हमारे कई युवा साथी विदेश में अच्छा जाब भी छोड़कर हिंदुस्तान में ही कोई उद्यम या आजीविका पूरी ताकत से करते हुए गौरव का अनुभव कर रहे हैं। यह बदलाव शुभ संकेत हैं। 8 साल पहले मात्र 80-100 कृषि स्टार्टअप थे, वहीं प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी द्वारा लगातार प्रोत्साहन के परिणामस्वरूप आज इनकी संख्या दो हजार से भी अधिक है, जिनमें से सैकड़ों को कृषि मंत्रालय की योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण व आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई है। केंद्र सरकार का इन्हें 10 हजार करने का लक्ष्य है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार तकनीक को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार चाहती है कि हमारे स्टार्टअप विद्यमान चुनौतियों का समाधान करते हुए देश-दुनिया के काम आएं, इस दिशा में कृषि मंत्रालय के साथ ही कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग (डेयर) व भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) सहित अन्य संस्थाओं द्वारा पूरी शिद्दत से काम किया जा रहा है। तोमर ने कहा कि टेक्नालाजी का लोकव्यापीकरण होना जरूरी है, तभी जन-जन को इसका वास्तविक लाभ होगा, साथ ही तकनीक ऐसी हो कि जिसकी लागत आम लोग वहन कर सकें। स्टार्टअप को अपनी दिशा व क्षेत्र तय कर काम करना चाहिए, ताकि किसानों को इनके कार्यों का पूरा लाभ मिल सकें। देश-दुनिया की बढ़ती आबादी के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा के लिए भी काम करना चाहिए, साथ ही जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को देखते हुए भी समाधान की दिशा में काम करना होगा। स्टार्टअप दूरदृष्टि व पक्के इरादे के साथ नवाचार करें। प्रधानमंत्री के आह्वान के अनुरूप, देश की आजादी के 100 वर्ष होने तक देश को पूरी तरह से विकसित करने में हमें कामयाब होना है। तोमर ने कहा कि भारत सरकार इसके लिए स्टार्टअप के साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर खड़ी हुई है।

इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी व शोभा करंदलाजे भी उपस्थित थी। कृषि सचिव मनोज अहूजा व आईसीएआर के महानिदेशक डा. हिमांशु पाठक ने भी संबोधित किया। प्रारंभ में, देशभर से आए सैकड़ों स्टार्टअप के अनेक प्रतिनिधियों ने अपने महत्वपूर्ण सुझाव मंत्रीगण के समक्ष रखें। इससे पहले, केंद्रीय मंत्री तोमर ने दोनों राज्यमंत्रियों के साथ विभिन्न स्टाल का अवलोकन कर स्टार्टअप से जानकारी ली।

'ऑनलाइन बाल यौन शोषण के खिलाफ हमारे बच्चों को बचाने की लड़ाई बहुआयामी'

निरंतर वैश्विक तकनीकी-मंथन से अमृत और विष दोनों निकले हैं। हमने खुशी के साथ अमृत का स्वागत किया है, लेकिन हाइड्रा जैसे विभिन्न सिर वाला विष, गंभीर और तत्काल चिंता का विषय है। अपराध को, आम तौर पर, अब वैश्विक नेटवर्क के सहारे अंजाम दिया जा रहा है- नशीली दवाओं की तस्करी, मानव तस्करी, आतंकवाद, बाल शोषण आदि की कोई भौगोलिक सीमा नहीं है। लेकिन, सबसे भयावह, घृणास्पद, क्रूर और घिनौना अपराध है- ऑनलाइन बाल यौन शोषण। दुःख की बात है कि यह तेजी से बढ़ रहा है- गुप्त रूप में तथा कपटपूर्ण और गुमनाम तरीके से। एक अपमानजनक सच्चाई यह है कि तस्वीरें और वीडियो अनगिनत हैं-

जो अक्सर क्षति न पहुंचानेवाले कवर के तहत होते हैं- तथा ये इंटरनेट से जुड़े सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर सोशल नेटवर्किंग और संबद्ध वेबसाइटों के जरिये उपलब्ध हैं। कूट भाषा नेटवर्क, इन विकृत अपराधियों का व्यावहारिक रूप से पता लगाना मुश्किल बनाते हैं। इस अत्यधिक हानिकारक खतरे को दर्शाने के लिए 'चाइल्ड पोर्न', 'किड पोर्न' या 'पोर्नोग्राफी' आदि शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। प्रत्येक तस्वीर या वीडियो के पीछे, एक वास्तविक बाल पीड़ित है, वास्तविक शोषण है और एक अपराध है। इस तरह की सामग्री का निरंतर निर्माण व वितरण नए और अधिक खुले तस्वीरों की मांग को बढ़ावा देता है, जिससे नए बच्चों के साथ दुर्व्यवहार का चक्र चलता रहता है। ऑनलाइन बाल यौन शोषण के खिलाफ हमारे बच्चों को बचाने की लड़ाई बहुआयामी है, जिनमें उल्लंघन का अपराधीकरण, रोकथाम, सक्रिय पहचान, आपराधिक जांच, प्रसार पर अंकुश लगाना, पीड़ित की पहचान/पुनर्स्थापन और अपराधी पर मुकदमा चलाना शामिल हैं। ऑनलाइन स्वीकार्य व्यवहार क्या है और क्या नहीं है- इंटरनेट तक पहुंच रखने वाले किसी भी बच्चे को, इसके बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए।

हमें अपने बच्चों को कई उन विकृत व्यवहारों और खतरनाक स्थितियों के बारे में शिक्षित करना होगा, जो उनके सामने ऑनलाइन आ सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ऐसी सामग्री का सक्रिय रूप से पता लगाने और उसे प्रतिबंधित करने के लिए नियम व तौर-तरीके विकसित कर रहे हैं। ये निश्चित रूप से समाधान का हिस्सा हैं, लेकिन अपराध की जांच और अभियोजन का महत्व हमेशा की तरह महत्वपूर्ण है। भारत, दुनिया में बच्चों की सबसे बड़ी आबादी वाले देशों में एक है। 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में अठारह

लेखक :
आरके शुक्ला,
सीबीआई के पूर्व निदेशक

वर्ष से कम उम्र के 472 मिलियन बच्चे हैं, जिनमें से 225 मिलियन लड़कियां हैं। भारत में डिजिटल पहुंच भी तेजी से बढ़ रही है। इससे अपराध होने की संभावना बढ़ जाती है। भारत में, आईटी अधिनियम और पॉक्सो के माध्यम से ऑनलाइन बाल यौन शोषण को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। पॉक्सो बच्चों को सर्वाधिक महत्व देता है और इसके लिए बच्चों के सम्बन्ध में अनुकूल रिपोर्टिंग, साक्ष्य को रिकॉर्ड करना, जांच करना और विशेष न्यायालयों के माध्यम से अपराधों के त्वरित परीक्षण के लिए एक मजबूत कानूनी फ्रेमवर्क प्रदान करता है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) पोस्को कार्यान्वयन की स्थिति की निगरानी करता है। भारत में कानून प्रवर्तन एजेंसियां, इंटरपोल और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सक्रिय संपर्क के माध्यम से, ऑनलाइन बाल शोषण के खिलाफ लड़ाई के लिए प्रतिबद्ध हैं। सामग्री को रोकने और जानकारी साझा करने के अलावा, अपराधों की जांच को भी उच्च प्राथमिकता दी जाती है। सीबीआई ने ऑनलाइन बाल यौन शोषण सामग्री के बारे में जानकारी एकत्र करने, मिलान करने, जांच करने और इसे बड़े पैमाने पर लागू करने के लिए एक समर्पित प्रकोष्ठ की स्थापना की है। इस खतरे से लड़ने की प्रतिबद्धता के अनुरूप, सीबीआई बाल यौन शोषण सामग्री (आईसीएसई) के बारे में सहयोग प्राप्त करने के लिए इंटरपोल द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय बाल यौन शोषण (सीएसएएम) डेटाबेस में शामिल हो गई है।

भारत इस डेटाबेस में शामिल होने वाला 68वां सदस्य देश है। डेटाबेस में 27 लाख से अधिक तस्वीरें हैं और इससे 23,000 से अधिक पीड़ितों की पहचान करने में मदद मिली है। इंटरपोल के महासचिव ने हाल ही में डेटाबेस की उपयोगिता के बारे में कहा है कि यह दैनिक आधार पर औसतन 07 पीड़ितों की पहचान करता है। यह महसूस करते हुए कि संयुक्त व समन्वित खुफिया आधारित कार्रवाई, संचालन प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण हैं, सीबीआई ने हाल के वर्षों में अखिल भारतीय अभियान चलाए हैं। 2021 में ऑपरेशन कार्बन और 2022 में ऑपरेशन मेघ चक्र। दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य यह है कि खतरा देश के सभी हिस्सों में फैल चुका है।

अब केवल इतना ही, दुनिया भर में 100 से अधिक न्यायालय क्षेत्राधिकारों में अपराध की मौजूदगी है। वास्तविक चुनौती इस कार्रवाई को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाने की है। फिर भी, एक देशव्यापी कार्रवाई लोगों के बीच जागरूकता फैलाने में बहुत मदद करती हैं। जब 100 से अधिक न्यायालय क्षेत्राधिकारों से जुड़े अपराधी एक जघन्य अपराध में बिना किसी बाधा के हाथ मिला सकते हैं, तो यह विडंबना ही है कि कानून प्रवर्तन को एक विश्वसनीय और समन्वित जवाबी कार्रवाई करने में न केवल महीनों बल्कि वर्षों का समय लग जाता है। पारस्परिक कानूनी सहायता में देरी होती है। कानून प्रवर्तन एजेंसियों को क्षेत्रीयता के कारण जांच के लिए वास्तविक समय पर कार्रवाई योग्य डेटा का अभाव, अधिकार क्षेत्रों में डेटा साझा करने का जटिल तंत्र, अपराधियों द्वारा बेनामी/छद्म नाम/वीपीएन/समान तकनीक वाले नेटवर्क का उपयोग, नकली आईडी का उपयोग आदि बाधाओं का भी सामना करना पड़ता है। ऑनलाइन बाल शोषण की तुलना अन्य अपराधों से नहीं की जा सकती। नीति निर्माण और कानून प्रवर्तन को क्षेत्रीय बाधाओं, कानूनी विषमताओं और जटिल प्रक्रियाओं में फंसने की बजाय समाधान ढूंढने की जरूरत है। एक जिम्मेदार वैश्विक समुदाय के रूप में, हमें अपने सभी मतभेदों को दूर करना चाहिए और इस खतरे के खिलाफ एक वास्तविक वैश्विक प्रयास के साथ एक ठोस जवाबी कार्रवाई की जानी चाहिए। वर्तमान में, इंटरपोल कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच विश्व स्तर पर विश्वास-निर्माण कर सकता है। इसकी स्थिति सबसे अच्छी है- गहरी पैठ के साथ साझेदारियों की विस्तृत श्रृंखला। दिल्ली में आयोजित होने वाली इंटरपोल की आम सभा को मुख्य रूप से इस मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिससे यह सर्वोच्च प्राथमिकता बन जाए। हमारे बच्चे सबसे पहले- हर बार, हर जगह। यह वैश्विक समुदाय के लिए आदर्श वाक्य और लक्ष्य होना चाहिए।

हिटलर जैसी है बाइडन की सोच, तुलसी गबार्ड ने यूक्रेन हमले का भी मढ़ा दोष

भारतीय मूल की अमेरिकी नेता तुलसी गबार्ड ने राष्ट्रपति जो बाइडन पर कड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने यूएस राष्ट्रपति की तुलना बाइडेन से करते हुए कहा है कि उन्हें बाइडन व हिटलर की मानसिकता एक जैसी दिखती है।

• **जालंधर ब्रीज.** वर्ल्ड न्यूज

भारतीय मूल की अमेरिकी नेता तुलसी गबार्ड ने राष्ट्रपति जो बाइडन पर कठोर टिप्पणी की है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना बाइडेन से करते हुए कहा है कि उन्हें बाइडन और हिटलर की मानसिकता एक जैसी नजर आती है। गौरतलब है कि तुलसी गबार्ड अमेरिकी संसद की पूर्व सदस्य रही हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, गबार्ड 2020 में व्हाइट हाउस की दौड़ में शामिल रहीं पहली हिंदू अमेरिकी नेता हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, गबार्ड ने रूस पर यूक्रेन हमले की जिम्मेदारी भी बाइडेन पर मढ़ डाली है।

सत्ताधारी दल से हटने के बाद : तुलसी गबार्ड ने सत्ताधारी डेमोक्रेटिक पार्टी से बाहर होने की घोषणा करने के कुछ दिन बाद बाइडन की तुलना एडोल्फ हिटलर से की है। पिछले साल प्रतिनिधि सभा से सेवानिवृत्त हुई 41 वर्षीय गबार्ड ने आठ नवंबर को होने वाले मध्यावधि चुनाव के प्रचार अभियान के दौरान यह टिप्पणी की। 'द डेली बीस्ट' अखबार के अनुसार, रविवार को मैनचेस्टर के बाहर एक शहर में बोल्डुक टाउन हॉल कार्यक्रम में बोलते हुए हवाई की पूर्व कांग्रेस सदस्य ने कहा कि उन्हें बाइडन और हिटलर की मानसिकता एक जैसी नजर आती है।

यूक्रेन हमले पर कही यह बात : पिछले हफ्ते गबार्ड ने घोषणा की थी कि वह डेमोक्रेटिक पार्टी छोड़ रही हैं। गबार्ड 2013 में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के लिए हवाई से चुनी जाने वाली पहली हिंदू थीं, और बाद में वह लगातार चार बार चुनी गईं। गबार्ड ने यह भी कहा कि रूस ने जो यूक्रेन पर हमला किया है, उसके पीछे असल में बाइडेन की फेल होती विदेश नीति है।

बिहार के स्कूल के पेपर में कश्मीर को बता दिया अलग देश, नीतीश कुमार पर फायर हुई भाजपा

• **जालंधर ब्रीज.** नई दिल्ली

बिहार में कक्षा 7 के अंग्रेजी के पेपर में कश्मीर को लेकर पूछे गए विवादित प्रश्न पर सियासी बवाल मच गया है। नीतीश सरकार बीजेपी के निशाने पर आ गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार के सरकारी अफसर सीमांचल के बच्चों में अलगाववादी मानसिकता का पोषण कर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश को चेतावनी देते हुए कहा कि वे बीजेपी से लड़े भारत से नहीं।

संजय जायसवाल ने बेतिया में कहा कि बीते शनिवार को अद्धवार्षिक परीक्षा में पूर्णिया, किशनगंज व अररिया में 7वीं

के बच्चों से विवादित सवाल पूछा गया था। पेपर में लिखा था कि चीन में रहने वाले को चायनीज तो नेपाल, इग्लैंड, भारत और कश्मीर में रहने वाले को क्या कहेंगे? इसमें कश्मीर को अलग देश बताया गया। 2017 में भी यह सवाल पूछा गया था। तब कार्रवाई की बात सरकार की ओर से कही गई थी, लेकिन आज तक सवाल सेट करने वाले अपराधी अफसरों पर कार्रवाई नहीं हुई। यह शर्जिल इमाम के एजेंडे पर चिकन नेक को पकड़ नॉर्थ ईस्ट को अलग करने को लागू करने की साजिश है। जायसवाल ने कहा कि सीमांचल के बच्चों से यह प्रश्न पूछने वाले का बीजेपी कदम-कदम पर विरोध करेगी। भाजयुमो इसको लेकर राज्यभर में प्रदर्शन करेगा। उन्होंने सीएम नीतीश पर आरोप लगाया कि शिक्षा सचिव एवं प्रधान सचिव की मिलीभगत से गजवा-ए-हिन्द पर भी प्रश्न सेट किए जाएंगे।

बीजेपी नेता संजय जायसवाल ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि सीएम नीतीश बीजेपी से लड़ें, न कि भारत से। वे देश विरोधी ताकतों से मिलकर काम कर रहे हैं। महागठबंधन पीएफआई समर्थक सरकारी अफसर और आरजेडी के पीएफआई समर्थकों के गठबंधन का नतीजा है।

मैं क्या करता हूं, यह आपको जानना चाहिए; विदेश मंत्री जयशंकर की युवाओं से अपील

एस जयशंकर ने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में पिछले आठ वर्षों में बहुत कुछ बदल गया है। उन्होंने कहा, "हमारी विदेश नीति की तीन मुख्य परतें हैं। पहला सुरक्षा केंद्रित है। दूसरा विकास केंद्रित है।"

• **जालंधर ब्रीज.** नई दिल्ली

मोदी सरकार में विदेश मंत्री (ईएएम) एस जयशंकर ने मंगलवार को युवाओं को विदेशी मामलों में सक्रिय रुचि लेने के लिए प्रोत्साहित किया। गुजरात के अहमदाबाद में मोदी युग में भारतीय विदेश नीति विषय पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि लोग जानें कि एक विदेश मंत्री क्या करता है और विदेश नीति आज सभी को कैसे प्रभावित करती है। उन्होंने कहा, "मैं चाहूंगा कि आप समझें कि मैं क्या करता हूं। एक विदेश मंत्री के दो बड़े कार्य होते हैं। पहला भारत को दुनिया से परिचित कराना। साथ ही दुनिया को यह समझाना कि भारत नया क्या कर रहा है।"

एस जयशंकर ने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में पिछले आठ वर्षों में बहुत कुछ बदल गया है। उन्होंने कहा, "हमारी विदेश नीति की तीन मुख्य परतें हैं। पहला सुरक्षा केंद्रित है। दूसरा विकास केंद्रित है। तीसरा जनता केंद्रित है।" कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि आज जो कुछ भी कहीं भी होता है वह दुनिया भर में सभी को प्रभावित करता है।

जयशंकर ने कहास "आज दुनिया के बारे में हमने जो दीवारें बनाई हैं वे टूटी हुई हैं। दुनिया में कहीं भी जो कुछ भी होता है उसका प्रभाव

हर जगह महसूस किया जाता है। यूक्रेन में युद्ध और कोविड महामारी दिखाती है कि दुनिया का हम पर क्या प्रभाव है। इसने हमें किसी विशेष देश पर निर्भर नहीं होने के बारे में सिखाया है। हमें वैश्विक कार्यस्थल और वैश्विक बाजार को बढ़ाना होगा।"

विदेश मंत्री ने कहा कि पिछले 20-30 वर्षों में जब दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही थी, तब भारत पिछड़ गया था। आज भारत में आई-फोन का निर्माण हो रहा है। अमेरिका और चीन के बदलते स्वरूप का जिक्र करते हुए जयशंकर ने कहा, "बदलती दुनिया में दो सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं 'राइजिंग चाइना' और 'चेंजिंग यूएस' हैं। चीन आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य रूप से आगे बढ़ा है। अमेरिका ने अपने संबंधों और साझेदारियों को लेकर बदलाव किया है।" विदेश मंत्री ने आगे कहा कि आतंकवाद और सीमा मुद्दों को लेकर पिछले आठ सालों में भारत के रवैये में काफी बदलाव आया है।

उन्होंने कहा, "हम सभी जानते हैं कि भारत हमेशा आतंकवाद का शिकार रहा है। लेकिन अब इसके बारे में हमारा दृष्टिकोण बदल गया है। आप इसकी तुलना 2008 में मुंबई, इसके बाद उरी और पुलवामा में हुई घटनाओं से कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि अपनी नीतियों को लेकर हमारी सरकार कितनी आश्वस्त है।"

पीने योग्य साफ़ पानी की सप्लाई पंजाब सरकार की मुख्य प्राथमिकता : जिम्पा

जल सप्लाई और सेनिटेशन मंत्री द्वारा विश्व बैंक की टीम के साथ अहम मीटिंग

• जालंधर ब्रीज.चंडीगढ़

मुख्यमंत्री भगवंत मान के गतिशील नेतृत्व अधीन पंजाब सरकार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों को पीने योग्य साफ़ पानी और सेनिटेशन सहूलतें मुहैया करवाने के लिए वचनबद्ध है। इस मकसद की पूर्ति के लिए जल सप्लाई और सेनिटेशन विभाग की तरफ से व्यापक यत्न किये जा रहे हैं। राज्य में जल सप्लाई प्रोजेक्टों को तेज़ी से लागू करने के यत्नों को जारी रखते हुये जल सप्लाई और सेनिटेशन मंत्री ब्रम शंकर जिम्पा ने विश्व बैंक की टीम और विभाग के अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय मीटिंग की अध्यक्षता की। मीटिंग में उन्होंने जल सप्लाई और सेनिटेशन सम्बन्धी प्रोजेक्टों को लागू करने में तेज़ी लाने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया जिससे उपभोक्ताओं को किफ़ायती दरों पर बेहतर सेवाएं प्रदान की जा सकें।

विश्व बैंक की टीम ने मंत्री को विश्व बैंक की तरफ से दिए जाने वाले सहयोग और वित्तीय सहायता के बारे जानकारी दी। टीम ने बताया कि जल सप्लाई और सेनिटेशन विभाग और विश्व बैंक ने सांझे तौर पर व्यापक यत्न किये हैं जिसके परिणामस्वरूप् ग्रामीण लोगों को पीने योग्य पानी उनकी ड्योढ़ी पर उपलब्ध करवा के ज़िंदगी में सकारात्मक तबदीली लाई है।

जल सप्लाई और सेनिटेशन विभाग के प्रमुख सचिव डी. के. तिवारी ने मंत्री को अवगत करवाया कि विभाग ने विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से मोगा में 218 करोड़ रुपए की लागत के साथ एक बड़ा सरफेस वाटर सप्लाई प्रोजैक्ट शुरू किया है जो मोगा जिले के 85 गाँवों के करीब 3. 54 लाख निवासियों को पीने योग्य साफ़ पानी मुहैया करवा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि विभाग की तरफ से अमृतसर, गुरदासपुर, तरन तारन, फ़िरोज़पुर, फाजिल्का, होशियारपुर, पटियाला, रोपड़ और फतेहगढ़ साहिब जिलों में ऐसे 15 और प्रोजैक्ट भी जल्द लागू किये जा रहे हैं। इनमें से 5 प्रोजैक्टों के लिए विश्व बैंक की तरफ से और 10 प्रोजैक्टों के लिए नाबार्ड की तरफ से सहायता दी गई है। इन प्रोजैक्टों की कुल लागत 1700 करोड़ रुपए है।

खेड़ा वतन पंजाब दीयां : बास्केटबाल की अंडर-21 प्रतियोगिता में लुधियाना ने दोनों खिताब जीते

लड़कियों के मुकाबले में लुधियाना ने संगरूर को, लड़कों में जालंधर को हराया

• जालंधर ब्रीज.लुधियाना

पंजाब सरकार के खेल विभाग द्वारा आयोजित 'खेड़ा वतन पंजाब दीयां 2022' के अंडर-21 लड़के/लड़कियों की राज्य स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में जिला लुधियाना ने लड़कियों के मैच में संगरूर को हरा कर जबकि लड़कों के मैच में जालंधर को हरा कर जीत दर्ज की और खिताब अपने नाम किए। जिला खेल अधिकारी रविन्द्र सिंह ने बास्केटबॉल खेल के परिणामों की जानकारी साझा करते हुए कहा कि लुधियाना ने अंडर-21 वर्ग की लड़कियों की खेल प्रतियोगिता में संगरूर को 36-21 के अंतर से हराया। तीसरे स्थान पर कपूरथला ने पठानकोट को 37-10 के अंतर से हराया। इसके अलावा लड़कों की खेल प्रतियोगिता में लुधियाना ने जालंधर को 58-38 के अंतर से हराया, जबकि तीसरे स्थान पर रही फरीदकोट की टीम ने 72-65 के फर्क से मानसा के खिलाफ जीत हासिल की।

जिला खेल अधिकारी रविन्द्र सिंह ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा 'खेड़ा वतन पंजाब दीयां 2022' शुरू करके एक बहुत ही सराहनीय पहल की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार की इस पहल से नशा करने वाली युवा पीढ़ी को एक नई उम्मीद मिल रही है। इस मौके पर पंजाब बास्केटबॉल अकादमी (पीबीए) के महासचिव तेजा सिंह धालीवाल, खेल विभाग के संजीव शर्मा, पीबीए उपाध्यक्ष विजय चोपड़ा, अंतरराष्ट्रीय कोच सलोनी, जिलाध्यक्ष वीरपाल सिंह ढिल्लों, सुखविंदर सिंह, रविंदर सिंह गिल और नरेंद्र पाल भी मौजूद थे।

धान की बोगस व दूसरे राज्यों से अनाधिकृत धान लाने से रोकने के लिए उडऩ दस्ते गठित

• जालंधर ब्रीज.होशियारपुर

जिला मजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर संदीप हंस ने मौजूदा धान की खरीद के सीजन के दौरान कुछ शरारती तत्वों की ओर से धान य चावल की बोगस खरीद/दूसरे राज्यों से अनाधिकृत आने वाले धान/ चावल व गैर कानूनी रिसाइकिलिंग करने के खतरे के मद्देजनर जिले के अंदर मार्किट कमेटी स्तर पर उडऩ दस्ते गठित किए हैं। जिले की 5 मार्किट कमेटियों में 20 अधिकारी चैकिंग के लिए लगाए गए हैं।

जानकारी देते हुए डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि खाद्य आपूर्ति व उपभोक्ता मामले विभाग पंजाब के प्रमुख सचिव की ओर से प्राप्त हिदायतों के मुताबिक दूसरे राज्यों से अनाधिकृत आने वाले धान या चावल की आमद व गैर कानूनी गतिविधियां रोकने के लिए व मंडियों की औचक चैकिंग करने के लिए होशियारपुर जिले में अलग-अलग विभागों व पुलिस के अधिकारियों को शामिल कर उडऩ दस्तों का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि इन उडऩ दस्तों में ई.टी.ओ, नायब तहसीलदार, सचिव मार्किट कमेटी व मुख्य थाना अधिकारी को शामिल किया गया है। इसी तरह मंडियों में धान की आमद व खरीद संबंधी सभी एस.डी. एम्ज, मुख्य कृषि अधिकारी व जिला मंडी अधिकारी के नेतृत्व में कमेटी का गठन किया गया है। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि यह आदेश जिला पुलिस प्रमुख, समूह एस.डी.एम्ज, जिला मंडी अधिकारी, सहायक कमिश्नर कर व आबकारी विभाग, जिला कंट्रोलर खाद्य आपूर्ति व उपभोक्ता मामले, समूह तहसीलदार व नायब तहसीलदारों को भेज कर अगली कार्रवाई अमल में लाने के निर्देश दिए गए हैं।

संदीप हंस ने कहा कि यह उडऩ दस्ते हर मार्किट कमेटी स्तर पर दूसरे राज्यों से अनाधिकृत आने वाले धान, चावल की चैकिंग करेंगे व मार्किट कमेटी स्तर की मंडियों में समय-समय पर चैकिंग करते हुए गैर कानूनी धान व चावल पाए जाने पर ट्रक या गुदाम जब्त कर कानूनी कार्रवाई करते हुए रिपोर्ट डिप्टी कमिश्नर कार्यालय को भेजेंगे।

ई-सेवा पोर्टल से जारी होने वाले सर्टिफिकेट, दस्तावेज अब लोग अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर कर सकेंगे डाउनलोड

पंजाब सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से आम लोगों को ई-सेवा पोर्टल के माध्यम से प्रमाणित किए जाते सर्टिफिकेट, दस्तावेजों की प्राप्ति के लिए सेवा केंद्रों में बार-बार जाने की मुश्किल को आसान करते हुए, अब से यह सर्टिफिकेट, दस्तावेज उनके मोबाइल, ईमेल पर भेजे लिंक के माध्यम से डाउनलोड करने की सुविधा दे दी है। डीसी संदीप हंस ने बताया कि पहले सेवा केंद्र या ई-सेवा पोर्टल के माध्यम से मांगी गई सेवा से संबंधित दस्तावेज तैयार होने पर सेवा केंद्र से होलोग्राम लगा कर जारी किया जाता था। अब सरकार ने लोगों की बार-बार सेवा केंद्र में आने की मुश्किल को हल करते हुए उनको घर बैठे ही अपनी सेवा से संबंधित सर्टिफिकेट, दस्तावेज को मोबाइल, कंप्यूटर से डाउनलोड करने की सुविधा दे दी है।

डीसी ने बताया कि सरकार की ओर से जारी हिदायतों के अनुसार अब ई-सेवा पोर्टल के माध्यम से डिजिटल साइन होने वाले सर्टिफिकेट, दस्तावेजों पर किसी भी तरह के भौतिक हस्ताक्षर, मुहर या होलोग्राम की जरुरत नहीं होगी। ई-सेवा पोर्टल के माध्यम से डिजिटल हस्ताक्षर किए गए सर्टिफिकेट, दस्तावेजों की वैरिफिकेशन या प्रमाणिक वैब लिंक https://esewa.punjab.gov.in/certificateVerification पर दस्तावेज का सीरियल नंबर दर्ज कर या सर्टिफिकेट, दस्तावेज के मौजूदा क्यू.आर.कोड को स्कैन कर किया जा सकता है। उक्त वैरीफिकेशन वैब लिंक पर उपलब्ध विवरण व सर्टिफिकेट, दस्तावेज पर दर्ज विवरणों की तुलना में यदि कोई भी अंतर पाया जाता है तो वह सर्टिफिकेट, दस्तावेज को अयोग्य समझा जाएगा। उन्होंने बताया कि सेवा केंद्रों में अपनी सेवा के लिए प्रार्थना पत्र देने वाला कोई भी प्रार्थी सर्टिफिके, दस्तावेज के डिजिटल साइन होने से बाद प्रार्थना पत्र में दिए गए मोबाइल नंबर व ईमेल पर वैब लिंक प्राप्त करेगा, जहां सीधे तौर पर सर्टिफिकेट, दस्तावेज को डाउनलोड किया जा सकता है।

अस्थायी लाइसेंस के बिना पटाखे बेचने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

• जालंधर ब्रीज.होशियारपुर

डीसी संदीप हंस ने कहा कि जिले में अस्थायी लाइसेंस के बिना कोई भी दुकानदार पटाखे नहीं बेचेगा और जारी किए गए एक लाइसेंस पर केवल निर्धारित किए गए स्थानों पर ही पटाखे बेचे जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि जारी किए गए अस्थायी लाइसेंस व निर्धारित स्थानों के अलावा अगर कोई पटाखा विक्रेता पटाखा बेचता पाया गया, तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि 10 अक्टूबर को जिला प्रशासन होशियारपुर की ओर से रिटेल पटाखे बेचने के लिए जिले में 19 स्थानों के लिए 57 लोगों को पारदर्शी तरीके से ड्रा के माध्यम से अस्थायी लाइसेंस जारी किए थे। इस लिए केवल अस्थायी लाइसेंस धारक व्यक्ति ही जिला प्रशासन की ओर से बताई शर्तों के अनुसार निर्धारित स्थानों पर पटाखे बेच सकते हैं।

डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि उनके ध्यान में आया है कि जिले में कुछ व्यक्ति बिना लाइसेंस के पटाखे बेच रहे हैं और अगर इन स्थानों पर पटाखों के कारण कोई अप्रिय घटना होती है, तो उक्त विक्रेता स्वयं उसके जिम्मेदार होंगे। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन के अधिकारी अलग-अलग स्थानों पर चैकिंग की जा रही है और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई भी की जाएगी।

पशुओं के प्रति बेरहमी रोकने के लिए जिला एसपीसीए का गठन

• जालंधर ब्रीज.जालंधर

पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकने और उनका कल्याण सुनिश्चित करने के लिए डिप्टी कमिशनर की अध्यक्षता में जिला सोसायटी फार प्रीवेशन आफ क्रुरैलिटी (एसपीसीए) का गठन किया गया है, जिसकी पहली बैठक में अतिरिक्त डिप्टी कमिशनर (विकास) वरिंदरपाल सिंह बाजवा ने समिति के सदस्यों के साथ पशु कल्याण से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से विचार चर्चा की। स्थानीय जिला प्रशासकीय परिसर में बैठक के दौरान एडीसी ने कहा कि जिला एसपीसीए का उद्देश्य जानवरों के अधिकार, स्वतंत्रता, कल्याण, सुरक्षा सुनिश्चित करना और उनके साथ क्रूरता के मामलों का समाधान करना है। उन्होंने समिति के सदस्यों से जानवरों के प्रति क्रूरता को रोकने के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार करने और लागू करने की बात भी कही। इस बीच पशुओं के लिए शैलटर बीमार और घायल जानवरों को पशु चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करना, लोगों में पशु कल्याण और दया-भावना को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता पैदा करना एसपीसीए के लिए जमीन अलाटमैंट सहित विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा हुई।

नेहरू युवा केंद्र द्वारा जागरूकता रैली आयोजित, सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करने प्रति लोगों को किया जागरूक

• जालंधर ब्रीज.कपूरथला

जिला युवा अधिकारी नेहरू युवा केंद्र कपूरथला गगनदीप कौर के नेतृत्व में डीसी चौक कपूरथला से सुल्तानपुर लोधी रोड तक एक विशेष जागरूकता रैली का आयोजन किया गया ताकि स्वच्छ भारत 2.0 मिशन के तहत लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करने प्रति जागरूक किया जा सके। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए जिला युवा अधिकारी नेहरू युवा केंद्र गगनदीप कौर ने कहा कि इस जागरूकता रैली का मुख्य उद्देश्य लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक (जिसे एक बार इस्तेमाल के बाद फैंक दिया जाता है) का उपयोग नहीं करने के बारे में जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। और इस प्लास्टिक का पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि 19 प्रकार के 'सिंगल यूज प्लास्टिक' (प्लास्टिक की स्टिक वाली ईयर बड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की छड़ें, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, सजावट के लिए पालीस्टाइनिन (थर्मोकोल), प्लेट, कप, गिलास, कटलरी का निर्माण जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, पाइप, मिठाई के डिब्बे, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट के पैकेट के चारों प्लास्टिक पैकिंग या पैकिंग वाली फिल्में, 100 माइक्रोन से कम प्लास्टिक या पीवीसी बैनर, स्टिकर निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग सख्ती से प्रतिबंध लगाया गया है।

नेहरू युवा केंद्र के स्वयंसेवकों और युवा क्लब के सदस्यों ने लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक इकट्ठा कर इसका इस्तेमाल बंद करने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर नेहरू युवा केंद्र, परमजीत सिंह, लव कुमार, अमरजीत सिंह, गुरविंदर सिंह, अंजलि, सिमरन आदि के स्वयंसेवक मौजूद थे।

कपूरथला जिले में धान की खरीद निश्चित लक्ष्य के आधे से ज्यादा पूरी

किसानों को 662 करोड़ रुपये का भुगतान

• जालंधर ब्रीज.कपूरथला

कपूरथला जिले में 398581 मीट्रिक टन धान खरीदा गया है, जोकि निश्चित लक्ष्य का 50.07 प्रतिशत है। चालू सीजन दौरान कपूरथला जिले में कुल खरीद लक्ष्य 796120 मीट्रिक टन है। डिप्टी कमिशनर विशेष सारंगल ने कहा कि धान की खरीद उचित ढंग से चल रही है साथ ही लिफ्टिंग और भुगतान भी निर्धारित समय से पहले किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 19 अक्तूबर तक किसानों को 662.01 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि किसानों को खरीदी गई फसल की 48 घंटे में की जाने वाली अदायगी 638.72 करोड के मुकाबले किसानों के खाते में 662.01 करोड़ रुपये भेजी जा चुकी है, जो कि 103.66 प्रतिशत है। इसके इलावा लिफ्टिंग के मामले में जिले में 3 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की उठाई हो चुकी है और निर्धारित 72 घंटे की समय सीमा में 277904.06 मीट्रिक टन के मुकाबले जिले में 301028.513 मीट्रिक टन की चुकाई की गई है, जोकि 108.32 प्रतिशत है।

अब रोजर बिन्नी ने टीम इंडिया के पाक दौरे को लेकर कही बड़ी बात

मुंबई. बीसीसीआई सचिव जय शाह के एक बयान को लेकर बवाल मचा हुआ है। जय शाह ने कहा था कि भारतीय टीम एशिया कप 2023 के लिए पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगी। इसके साथ ही एशिया कप को न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाने की उन्होंने बात कही थी। अब इसी पर पूरा बवाल मचा हुआ है। पाकिस्तान की ओर से लगातार धमकी दी जा रही है। पूरे बवाल के बीच अब बीसीसीआई के नवनिर्वाचित अध्यक्ष रोजर बिन्नी का भी बयान आ गया है। उन्होंने टीम इंडिया के पाकिस्तान दौरे को लेकर साफ तौर पर कहा है कि यह हमारे हाथ में नहीं है। हम यह नहीं कह सकते कि हमारी टीम को कहां जाना है।

रोजर बिन्नी ने कहा कि अगर हम देश छोड़ते हैं या अन्य देश को जाते हैं या फिर कहीं से आते हैं तो हमें सरकार से मंजूरी लेनी होती हैं। अपने दम पर हम यह निर्णय नहीं ले सकते हैं। हमें सरकार पर भरोसा करना होगा। इससे पहले आज इसी मुद्दे पर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का भी बयान आया था। अनुराग ठाकुर ने साफ तौर पर कहा था कि खिलाड़ियों की सुरक्षा सर्वोच्च है। उन्होंने भी कहा था कि टीम इंडिया के पाकिस्तान दौरे को लेकर फैसला गृह मंत्रालय करेगा। इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय संस्थाओं को लेकर साफ तौर पर कहा कि हमारा रूख पहले दिन से स्पष्ट है कि आतंकवाद के साये में क्रिकेट नहीं खेला जा सकता। आपको बता दें कि 2008 के बाद पाकिस्तान का टीम इंडिया ने दौरा नहीं किया है। वहीं पाकिस्तान की टीम आखिरी बार 2012 में भारत आई थी। जय शाह के इसी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा था कि इस तरह के बयान एशियाई और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट समुदायों को विभाजित कर सकते हैं और 2023 विश्व कप के लिए पाकिस्तान की भारत यात्रा को भी प्रभावित कर सकते हैं। बयान के अनुसार, ''पीसीबी को अब तक एसीसी अध्यक्ष के बयान पर एसीसी की ओर से कोई आधिकारिक संवाद या स्पष्टीकरण नहीं मिला है। पीसीबी ने अब एशियाई क्रिकेट परिषद से आग्रह किया है कि वह महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा के लिए व्यावहारिक रूप से जितना जल्दी संभाव हो अपने बोर्ड की आपात बैठक बुलाए।''

डिप्टी कमिशनर ने कर्मचारियों के साथ सांझा की दीवाली की खुशियाँ

• जालंधर ब्रीज.जालंधर

डीसी जसप्रीत सिंह ने आज जिला प्रशासकीय परिसर में कार्यरत कर्मचारियों के साथ दीपावली के पावन पर्व की खुशी सांझा की और उन्हें उपहार बाँटे। डिप्टी कमिशनर ने स्थानीय जिला प्रशासकीय परिसर में एक साधारण समारोह के दौरान कर्मचारियों को उपहार बाँटते हुए दीपावली के पावन पर्व की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि दीपावली दीपों का त्योहार है, जिसे खुशियां बाँटकर मनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दीपों का त्योहार दीपावली न केवल हर घर को रोशन करता है बल्कि अंधकार पर प्रकाश की जीत, बुराई पर अच्छाई और निराशा पर आशा की जीत का भी प्रतीक है। डिप्टी कमिशनर ने यह भी कहा कि दिवाली के अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा एक विशेष पहल तौर पर अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत शहरवासी जरूरतमंद बच्चों के लिए खिलौने दान कर सकते है। उन्होंने कहा कि इसके लिए जिला प्रशासकीय परिसर स्थित सर्विस सेंटर और जिला बाल सुरक्षा इकाई कपूरथला चौक पर बॉक्स लगाए गए है, जहां शहरवासी नए या पुराने खिलौने दान कर सकते है। उन्होंने शहरवासियों को 23 अक्तूबर तक चलने वाले इस अभियान में बढ़-चढ़कर भाग लेने का न्योता देते हुए कहा कि यह दीपावली जरूरतमंद बच्चों को खुशियां देकर मनाई जानी चाहिए।

कार्तिक मास के उपलक्ष्य में निकाली प्रभातफेरी

• जालंधर ब्रीज.जालंधर

श्री चैतन्य महाप्रभु राधा माधव मंदिर प्रताप बाग में कार्तिक मास के उपलक्ष 15वीं प्रभातफेरी रामदेव वर्मा व मनीष वर्मा के निवास स्थान विक्रमपुरा से निकाली गई। सुबह संकीर्तन का शुभारंभ केवल कृष्ण, रेवती रमन गुप्ता, राजेश शर्मा, मिंटू कश्यप, मनोज कौशल, सुरेश कुमार और करतार सिंह द्वारा गुरु वंदना, वैष्णव वंदना और पंचतत्व द्वारा किया गया। प्रभात फेरी के मार्ग में माता चिंतपूर्णी मंदिर व विक्रमपुरा मोहल्ला वासियों की तरफ से पुष्प वर्षा कर प्रभातफेरी का स्वागत किया गया। प्रभात फेरी में लूट लूट लो नसीबा वालेओ लूट पै गई हरीनाम दी व हरे कृष्ण महामंत्र संकीर्तन द्वारा भक्तों ने बहुत नृत्य किया।

मंदिर के महासचिव राजेश शर्मा ने बताया कि 22 अक्टूबर की प्रभात फेरी मनोज कौशल के निवास स्थान दिलबाग नगर, व 23 अक्टूबर की प्रभात फेरी श्री अजय गोयल के निवास स्थान छोटी बारादरी बैक साइड ताज रेस्टोरेंट्स से आरंभ होगी। उन्होंने बताया कि 26 अक्टूबर को मंदिर में अन्नकूट महोत्सव बहुत हर्षोल्लास पूर्वक मनाया जाएगा। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक संकीर्तन होगा और भगवान को 56 भोग लगाएं जायेंगे। प्रभात फेरी में विवेक वर्मा,मनोज वर्मा, राजेश कनोजिया , सुनील कनौजिया, योगेश्वर शर्मा, जुगल मल्होत्रा, जितेंद्र चोपड़ा , हरीश , सूरी, हनी तलवार , अजय अग्रवाल, राजीव ढींगरा, प्रेम चोपड़ा, कपिल देव शर्मा , सनी दुआ, अश्विनी मिंटा, अमरजीत देओल, यशपाल अरोड़ा, राजन गुप्ता, सत्यव्रत गुप्ता , ओम भंडारी, रजिंदर लूथरा, नवल, गुरविंदर, संजीव खन्ना, चेतन दास, शशि भूषण, करणवीर, राजेश खन्ना, नरेंद्र कालिया, वैभव, नीरज कोहली, यांकिल कोहली, हेमंत थापर, अकाश मल्होत्रा, विजय सग्गड़, वनीत अरोड़ा, संजय पांडे, दिनेश विशाल भल्ला व अन्य शामिल हुए।

Printed, Published & Owner by ATUL SHARMA & Printed at SARANGLE PRINTERS, BASTI GUZAN JALANDHAR (PUNJAB) and Published from ATUL SHARMA, NN453 GOPAL NAGAR JALANDHAR (PUNJAB)
Editor : ATUL SHARMA*
*Responsible for selection of News under the PRB ACT. PUNHIN/2019/77863, All Rights Reserved. Reproduction in whole or in Part without permission is prohibited. All disputes shall be settled at Jalandhar jurisdiction only.